

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2731
उत्तर देने की तारीख: 11.12.2024

राजस्थान में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

†2731. श्री राहुल कस्वां:

क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के अंतर्गत अल्पसंख्यक क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के स्थायी कार्य किए जाते हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) राजस्थान में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत विगत पांच वर्षों के दौरान किए गए कार्यों की संख्या और इस संबंध में व्यय की गई राशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार का जैन समुदाय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए निधि जारी करने का विचार है क्योंकि राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में जैन समुदाय रहता है; और
- (ङ) यदि हां, तो यह निधि कब तक जारी किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रिजिजू)

(क) से (ङ.) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के तहत अधिसूचित सभी 6 (छह) अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला केन्द्रित परियोजनाएं, पेयजल और आपूर्ति, स्वच्छता और खेल जैसे क्षेत्रों में देश भर के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों (एमसीए) में सामुदायिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) को कार्यान्वित कर रहा है।

इस योजना का उद्देश्य देश में अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। पीएमजेवीके के तहत परियोजनाओं पर संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर विचार किया जाता है और उन्हें मंजूरी दी जाती है। परियोजना प्रस्तावों और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना, इस मंत्रालय को प्रस्तुत करना; स्वीकृत परियोजनाओं का कार्यान्वयन और पूरी की गई परियोजनाओं का संचालन और रखरखाव संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमजेवीके के अंतर्गत राजस्थान राज्य को स्वीकृत परियोजनाओं और जारी धनराशि का जिलावार ब्यौरा अनुबंध-1 पर है।

“राजस्थान में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम” के संबंध में श्री राहुल कस्वां द्वारा दिनांक 11.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2731 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

जिले का नाम	अनुमोदित इकाइयों की संख्या	कुल जारी धनराशि (लाख रुपये में)
अजमेर	8	768.09
अलवर	19	1730.36
बांसवाड़ा	3	232.91
बाड़मेर	1	165.39
भरतपुर	7	1039.15
बीकानेर	1	72.00
बूंदी	15	732.27
चित्तौड़गढ़	1	0.00
चुरू	6	162.79
गंगानगर	7	522.47
जैसलमेर	8	1059.97
झुंझुनू	3	168.62
नागौर	6	338.33
सवाईमाधोपुर	3	213.53
सीकर	2	311.27
टोंक	3	229.59
उदयपुर	2	627.28
